भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 2428**

**बुधवार, 08 अगस्त, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**आर्टिफिशियल इंटलिजेंस के संबंध में कृतिक बल**

**अता.प्र.सं. 2428. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डीः**

**श्रीमती अम्बिका सोनीः**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या मंत्रालय ने भारत के आर्थिक बदलाव के लिए आर्टिफिशियल इंटलिजेंस (एआई) के उपयोग को शुरू करने हेतु एआई के संबंध में एक कृतिक बल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भविष्य में इस उद्योग में अपनी पैठ बनाने के लिए देश में ही एआई के संबंध में शोध चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या एआई के प्रवेश के चलते रोजगारों तथा रोजगार की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री सी.आर. चौधरी)**

**(क),(ख)और(ङ):** भारत के आर्थिक कायान्तरण हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए आई) संबंधी एक कार्यबल का 24 अगस्‍त, 2017 को गठन किया गया था। कार्यबल ने 19 जनवरी, 2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत की थी। कार्यबल ने भारत में एआई से संबंधित क्रियाकलापों के समन्‍वय हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए, अन्‍य बातों के साथ-साथ, एक अंतर-मंत्रालयीय राष्‍ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के गठन की सिफारिश की है। कार्यबल की सिफारिशें सरकार के विभिन्‍न मंत्रालयों/विभागों को भेज दी गई हैं। कार्यबल ने नई नौकरियों की संभावना वाले क्षेत्रों यथा शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल, आई टी सेवाएं एवं बीपीओ की पहचान की है।

दिनांक 8 फरवरी, 2018 को आयोजित की गई सचिवों की समिति की बैठक में नीति आयोग को संबंधित मंत्रालयों/विभागों, शिक्षा-जगत तथा निजी क्षेत्र के साथ परामर्श करके एआई के लिए एक राष्‍ट्रीय कार्यनीति योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

नीति आयोग ने निम्‍नलिखित पांच क्षेत्रों पर ध्‍यान केन्‍द्रित करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्‍ट्रीय कार्यनीति संबंधी एक परिचर्चा दस्‍तावेज बनाया है तथा इसे दिनांक 04.06.2018 को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है:

1. स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल,
2. कृषि,
3. शिक्षा,
4. स्‍मार्ट सिटी तथा अवसंरचना,
5. स्‍मार्ट मोबिलिटी तथा परिवहन।

एक नीतिगत कार्य-ढांचे का निर्माण करने तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इकोसिस्‍टम विकसित करने के लिए इलेट्रोनिक्‍स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चार समितियों का गठन किया है जिसमें एआई के सभी पहलू शामिल हैं। ये समितियां निम्‍नलिखित हैं:-

1. एआई हेतु प्‍लेटफॉर्म तथा डाटा समिति,
2. प्रमुख क्षेत्रों में राष्‍ट्रीय मिशनों की पहचान करने के लिए एआई लेवरेजिंग समिति,
3. प्रौद्योगिकीय क्षमताओं के मापन, प्रमुख नीति एनेबलर, कौशल, पुर्नकौशल, अनुसंधान एवं विकास संबंधी समिति,
4. साइबर सुरक्षा, सुरक्षा, कानूनी तथा नीतिपरक मुद्दों संबंधी समिति।

**(ग) और (घ):** विभिन्न मंत्रालयों एवं एजेंसियों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर कार्य किया जा रहा है। उन्‍नत कम्‍प्‍यूटिंग विकास केन्‍द्र (सीडीएसी) मुख्‍य रूप से इमेज प्रोसेसिंग, ऑडियो सहायता, शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य, कृषि, परिवहन आदि पर ध्‍यान केन्‍द्रित करते हुए एआई क्षेत्र में कार्य कर रहा है। कृषि सहयोग तथा किसान कल्‍याण विभाग निजी क्षेत्र के साथ मिलकर फसल मानीटरिंग, उत्‍पादकों तथा उपभोक्‍ताओं को जोड़ने हेतु ब्‍लॉक-श्रंखला प्रौद्योगिकी, कीटों/बीमारियों की पहचान एवं मौसम आधारित फसल प्रबंधन प्रणाली जैसे क्षेत्रों के संबंध में कार्य कर रहा है। राजस्‍व विभाग प्रत्‍यक्ष एवं अप्रत्‍यक्ष करों के प्रशासन में प्रौद्योगिकियों संबंधी भविष्‍यवाणी हेतु डाटा एनालिटिक्‍स का उपयोग कर रहा है।

\*\*\*\*\*\*